







# विचार

# आखिर ब्राह्मणों ने बिगड़ा क्या है?

रोज सुबह-शाम ईश्वर की आराधना करते समय सबके कल्याण और विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करने वाले ब्राह्मणों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लिख कर वामपंथी सामाजिक तनाव फैलाने का प्रयास करते हैं तो कभी खबर आती है कि कर्नाटक में एक परीक्षा केंद्र में छात्रों से परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्हें जनेऊ उतारने के लिए कहा जाता है। कभी खबर देखने को मिलती है कि एक फिल्म निर्माता निर्देशक ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात खुलेआम कह देता है। देखा जाये तो हमारे देश की जाति व्यवस्था में ब्राह्मण को गुरु, पूज्य और यहाँ तक कि तीर्थस्वरूप माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो ब्राह्मण ही उसे संपन्न कराता है। पौराणिक ग्रंथों में तो उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को कभी निराश नहीं करना चाहिए और ब्राह्मणों को दिये जाने वाला दान-दक्षिणा जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करता है। लेकिन आज ब्राह्मणों के अपमान का फैशन-सा चल पड़ा है। चूंकि ब्राह्मण अपने हक के लिए या अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरते इसलिए सरकारों का ध्यान भी उनकी ओर नहीं जाता। देखा जाये तो इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने कभी विद्रोह नहीं किया ना ही अपने हक के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मण का प्रयास रहता है कि समाज में शांति और समृद्धि बनी रही। ब्राह्मणों के खिलाफ अक्सर अफवाहें और दुष्प्रचार अभियान भी चलाये जाते हैं लेकिन वह खामोशी से यह सोचते हुए सब कुछ देखते रहते हैं कि एक दिन प्रभु कृपा से सच सामने आ ही जायेगा। जहाँ तक कर्नाटक के शिवमोगा में सीईटी परीक्षा केंद्र आदिचुंचनगिरि पीयू कॉलेज में छात्रों से परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्हें जनेऊ उतारने के लिए कहने की बात है तो इसको देखकर हर कोई स्तब्ध है। कर्नाटक ब्राह्मण सभा के सदस्य नटराज भागवत की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। देखना होगा कि इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं लेकिन जिसने भी जनेऊ उतारने के लिए कहा या कहलवाया उसे पता होना चाहिए कि यज्ञोपवीत यानि जनेऊ ब्राह्मण को प्रदत्त महान शक्ति है। यह शक्ति अत्यन्त शुद्ध चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। यज्ञोपवीत न तो मोतियों का है और न स्वर्ण का, फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋग्न चुकाया जाता है। जिन्होंने छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा उन्हें पता होना चाहिए कि यज्ञोपवीत से सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गणों की पवित्रता प्राप्त होती है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने समेत श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है, इन सिफारिशों से न केवल यह योजना अधिक सशक्त एवं प्रभावी होकर ग्रामीण जनजीवन के कमज़ोर लोगों के लिये राहत का माध्यम बनेगी, बल्कि ग्रामीण जीवन को नये भारत की बुनियाद बनायेगी। मनरेगा भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब एवं कमज़ोर लोगों के लिए उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है और वर्तमान में यह भारत में सबसे मनरेगा पर न पड़े, इसलिये सरकार का यह सुझाव स्वागतयोग्य है की संतुष्टि, वेतन में देरी, बढ़ान और योजना वाली अनियमितताओं पर ध्यान देजाना चाहिए। इसीलिये समिति ने जुड़े कार्यक्रम की कमियों अहम जानकारी प्राप्त करने और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये नीतिगत सुधारों को लागू करने के देशभर में स्वतंत्र एवं पारदर्शी सिफारिश की है। समिति चुनौतियों के मद्देनजर योजना देने पर भी जोर दिया है। मनरेगा वक्त और उभरती चुनौतियों आज भी प्रासंगिक है।

बड़ा स्व-लक्ष्यकरण कायक्रम है। यह सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावशाली साधन है। जो नये भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत का आधार होगा।

मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है, बाबजूद मनरेगा में भी प्रष्टाचार, अफसरशाही, अनियमितता, कोताही के कारण इस महत योजना पर भी समय-समय अंधेरा छाता रहा है। यों तो गिरावट हर स्तर पर है। समस्याएं भी अनेक मुख्यरित हैं पर राष्ट्रीय चरित्र को विघटित करने वाले प्रष्टाचार एवं अनियमितता की काली छाया

# मुर्हिदाबाद हिंसा कांड पर कुछ अनुरागित सवाल

पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में वैसे तो वफ कानून का विरोध 08 अप्रैल से चल रहा था, लेकिन शुक्रवार 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद इलाके में माहौल अचानक तब बिगड़ गया, जब लगभग 150 लोगों ने मोहल्ले के निहत्थे और मासूम निवासियों जोरदार हमला कर दिया। जब 51 साल की बेबस और लाचार महिला जानकी मंडल ने फूट-फूट कर रोते हुए अपनी आंखों के सामने घटी घटना का टीवी पर वर्णन किया तो सचमुच बहुत दुःख हुआ। वह बता रही थीं कि बेकाबू भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगा दी।



पुरुषों को मारा-पीटा और सबकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी-बहुओं और माताओं का मान लूटने की कोशिश की। उग्र भीड़ में शामिल आतताइयों ने मोहल्ले वालों को धमकी दी कि भाग जाओ, वरना मरे जाओगे और लाचार मोहल्ले वाले चुपचाप यह सब देखते-सुनते रहे। फिलहाल, अपने ही देश में मालदा के वैष्णव नगर स्थित एक स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहीं जानकी मंडल ने यह भी बताया कि कैसे वह अपनी इज्जत और जान बचाकर बच्चों के साथ वहाँ से भागी र्थीं। बता दें कि यह पीड़ा केवल जानकी मंडल की नहीं, बल्कि वैष्णव नगर के स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहे लगभग 04 दर्जन हिंदू परिवारों की भी है, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता होगी कि मुर्शिदाबाद हिंसा कांड के सबसे अधिक पर्मिन्ट और दासी धनियाल नाम से जुड़ती ही है।

पांडित आर दुखा धुलियान कस्ब के लाग हा ह।  
 और ऐसा सोचने की भूल तो कदमपि नहीं करनी चाहिए कि इस भयावह पीड़ा और संत्रास वाली निमर्म घटनाओं की चैहद्दी धुलियान कस्बे तक ही सीमित है, बल्कि सच तो यह है कि मुर्शिदाबाद के विभिन्न इलाकों से आने वाली इस पीड़ा और संत्रास की आर्त चीखें दूर-दूर तक किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए हृदय विदारक रही हैं। जाहिर है कि दुःख-दर्द, निराशा, हताशा, बेबसी, लाचारी और आक्रोश से भरी बिल्कुल धुलियान के लोगों जैसी ही कहानियां कई अन्य इलाकों की भी हैं। टीवी चैनलों की भीड़ में एक चैनल पर अपश्रेयांत्र इलाके के पमेन्जीत टम्स ने भी रोटे-कलपत्रे द्वा

अपनी आपबीती तथा आंखों देखी घटनाएं टीवी पर बताई गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के मृतकों में से दो लोग प्रसेनजीत दास के परिवार से ही थे। मृतकों में एक उनका चर्चेरा भाई हरगोविंद दास और दूसरा भतीजा चंदन था। प्रसेनजीत ने जैसा टीवी पर बताया उसके अनुसार 10 अप्रैल की रात में लगभग 400 लोगों की भीड़ तलवार और छुरियां लहराते हुए मोहल्ले में घुसी। भीड़ में शामिल आताहियों ने 25 से 30 घरों, होटलों, दुकानों आदि में तोड़-फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। आंखों में भय भरकर प्रसेनजीत ने बताया कि भीड़ बहुत उग्र थी, इसलिए हमलोग उनसे भीड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जो कुछ वे करते रहे हमलोग चुपचाप देखते रहे।

उक्त घटना के सबैध में एक अन्य बहद खानफजदा व्यक्ति ने बताया कि भीड़ की उग्रता और आतंक इतना था कि कोई कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। इसलिए सभी अपनी-अपनी जान बचाकर भागने में ही लगे रहे। जाहिर है कि ये सभी आपबीती तथा आंखों देखी पीड़ि-व्यथाएं बिल्कुल सच्ची हैं। इनके अलावा, एक और सच, जिसे अब पूरी दुनिया जान और समझ चुकी है, वह यह कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी बंगाल सरकार की मुश्खिया ममता बनर्जी की 'ममता' अब तक नहीं जाग पाई है। जरा सोचिए, कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुरा इलाकों में दूर्व दिमांगों में कम-से-कम ०३ लोगों की जान चली

# ग्रामीणों की खुशहाली के लिये मनरेगा का सशक्तिकरण हो



व्यक्ति को मनरेगा के तहत 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।

मनरेगा एक बहुआयामी योजना है, जिसके तहत विभिन्न उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण सड़कें, और अन्य बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को रोजगार का दावा करने का अधिकार है। इस दूरगामी एवं ग्रामीण जनजीवन के उन्नयन एवं उत्थान के कार्यक्रम के लागू होने के बाद लाखों मजदूरों को काम मिला है। पलायन में काफी हद तक कमी आई। मनरेगा ने

लिए भी अपर्याप्त हैं। मजदूरी वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों और ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक प्रदान करें। रोजगार योजना के लिए आर्बाटिट राशि में लंबे समय से ठहराव पर समिति की चिंता इसी संदर्भ में है। कोई दो राय नहीं कि इसकी राशि बढ़ने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। समिति ने कहा, बदलते समय और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजना में सुधार की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय से उन विकल्पों पर विचार करने का आग्रह करती है, जिससे मनरेगा अधिक सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावी बन सके। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ग्रामीण विकास योजना को बल देने में सहायक है। हालांकि मनरेगा निरन्तर सवालों से घिरी रही है, इसमें वित्तीय अनियमितता की भी शिकायतें मिलती रही हैं। इसके प्रति श्रमिकों का रुझान घटने और मजदूरी देर से मिलने पर सवाल उठते रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की स्थायी समिति ने तीन साल पहले मनरेगा का विश्लेषण करते हुए कई सुझाव दिए थे। तब उस समिति ने भी इस कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए काम के गारंटीशुदा दिनों को सौ से बढ़ा कर डेढ़ सौ करने की सिफारिश की थी और सभी राज्यों में समान मजदूरी दर करने का सुझाव दिया था। अब संसद की समिति ने उन सुझावों पर एक तरह से मुहर लगाई है। अगर मनरेगा में नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी सर्वेक्षण होगा, तो इसके बेहतर परिणाम सामने

आएंगे। मनरेगा ने अपनी तार्किक सार्थकता साबित की है, लेकिन अभी इसमें व्यापक सुधारों की अपेक्षा है। देखने में आ रहा है मनरेगा से लाभान्वित लोगों को अक्सर बिना काम के ही राशि दी जा रही है, सरकार को इन लोगों की श्रम-शक्ति को देश-विकास के कार्यों में नियोजित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। मनरेगा योजना के अन्तर्गत कौशल विकास पर बल दिया

जाना चाहिए। योजना भले ही अकृशल श्रमिकों के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, लेकिन उन्हें अपने कौशल को विकसित करने और बढ़ाने का अवसर मिलने से यह योजना देश-विकास का माध्यम बन सकती है। वनीकरण, जल संरक्षण और सड़क निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं में उनकी भागीदारी से श्रमिकों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। वे नए कौशल सीख सकते हैं जिनका उपयोग मनरेगा द्वारा प्रदान किए जाने वाले भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए किया जाएगा। मनरेगा योजना सड़कों, नहरों, तालाबों और सिंचाई सुविधाओं जैसी परिसंपत्तियों के विकास का समर्थन करते हुए रोजगार प्रदान करें, इस योजना को कनेक्टिविटी, कृषि उत्पादकता, वन-विकास से भी जाड़ जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सके। जिससे ग्रामीण जीवन में नए मनुष्य का जन्म होगा।







